

divyadelhi.com

शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025

वर्ष: 12, अंक: 263, पृष्ठ: 08

₹ 05/-

दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

DD

दिव्य दिल्ली

जीएसटी धोखाधड़ी: ईडी का तीन राज्यों में 12 ठिकानों पर छापा

नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 750 करोड़ रुपये के फर्जी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चालान बनाने के मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में छापे मारे हैं। केन्द्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत तीनों राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 12 ठिकानों पर तलाशी ले रहा है। यह मामला फर्जी संस्थाओं और अनधिकृत वित्तीय चैनलों से जुड़े बड़े पैमाने पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय जांच एजेंसी की यह कार्यवाही शिव कुमार देवड़ा की गिरफ्तारी से शुरू हुई, जिसकी पहचान इस सिंडिकेट के मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में हुई है। मई, 2025 में उसकी गिरफ्तारी के बाद पिछले महीने उसे चार्जशीट किया गया था।

खाद्य तेल डेटा अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए आदेश में संशोधन

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने खाद्य तेल डेटा अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इससे खुदरा कीमतों को स्थिर करने और देशभर में खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन एवं उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 (वीओपीपीए विनियमन आदेश, 2011) में संशोधन को अधिसूचित किया है। यह आदेश मूल रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किया गया। इस आदेश को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 द्वारा पूर्ववर्ती विनियमों को निरस्त करने के बाद तैयार किया गया था। सुनिश्चित करने और सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों को समर्थन प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

उत्तराखंड: नौ साल में 18, 464 प्राकृतिक आपदाओं ने दिए जख्म



देहरादून
राज्य को नौ वर्षों में बड़ी संख्या में प्राकृतिक आपदाओं ने जख्म दिए हैं। अतिवृष्टि-त्वरित बाढ़ से लेकर बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं। इसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग राज्य में सड़क दुर्घटना, आग, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, कीट आक्रमण, हिमस्खलन, अतिवृष्टि-त्वरित बाढ़, व्रजपात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, डूबना, बहजाना, जंगली पशुओं का हमला, बादल फटना, वनाग्नि, बीमारी फैलना, विद्युत करंट, वनाग्नि की घटनाओं का विवरण तैयार करता है। इन घटनाओं में मृत्यु, घायल, लापता होने की सूचना एकत्र की जाती है। इसके अलावा मकानों के आंशिक और पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने का, रिकार्ड रखा जाता है। आपदा प्रबंधन विभाग के वर्ष 2015 से 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि

हर साल हजारों आपदा आ रही हैं। इसमें सबसे अधिक अतिवृष्टि-त्वरित बाढ़ के हैं, जिसकी 12758 घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा भूस्खलन भी चुनौती बना हुआ है। चार हजार से अधिक भूस्खलन की घटनाएं विभिन्न जिलों में हुई। बादल भी 67 बार फट चुके हैं। सबसे अधिक बादल फटने की घटना पैड़ी जिले में हुई है। राज्य में घटनाएं भूस्खलन-4654, बादल फटना-67, हिमस्खलन-92, आंधी तूफान-634, व्रजपात-259, अतिवृष्टि-बाढ़-12758, उत्तरकाशी में 1525 घटनाएं हुई, उत्तरकाशी में नौ साल में भूस्खलन, बाढ़, अतिवृष्टि-त्वरित बाढ़, हिमस्खलन, व्रजपात, ओलावृष्टि, बादल फटना, जंगल की आग समेत आदि की 1525 घटनाएं हुई हैं।

नई दिल्ली
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला है। उन्होंने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि- महाराष्ट्र में 40 लाख वोट रहस्यमयी तरीके से जोड़े गए हैं। राहुल गांधी का आरोप है लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच इन मतदाताओं को जोड़ा गया है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर राहुल गांधी हमलावर
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते कुछ समय से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ अन्य जगहों की मतदाता सूची के आधार पर चौंकाने वाले दावे किए हैं। मतदाता सूची में जोड़े गए हजारों-लाखों नाम का उल्लेख करते हुए राहुल ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन न करते हुए वोट की चोरी की जा रही है। उन्होंने कई आंकड़ों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है।

'भाजपा के लिए की जा रही है वोटों की चोरी'
राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुटाए गए सबूतों का जिक्र करते हुए कहा कि वोटों की चोरी



वोटों की चोरी पकड़ने में छह महीने का वक्त लगा- राहुल गांधी

इस दौरान राहुल गांधी ने सवाल पूछा- शाम पांच बजे के बाद वोटिंग क्यों बंद? चुनाव आयोग इसका जवाब दें। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वोटों की धांधली के मामले में चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं, लेकिन आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि हमें वोटों की चोरी पकड़ने में छह महीने का वक्त लगा है।

कर्नाटक में भी फर्जी मतदाता
भाजपा के लिए की जा रही है। मतदाता सूची के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि आयोग इस मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों मतदाताओं

होने का दावा
कांग्रेस सांसद ने महाराष्ट्र के अलावा एक अन्य राज्य को लेकर भी चौंकाने वाला दावा किया। बकौल राहुल गांधी, कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से अधिक वोटों की 'वोट चोरी' हुई। कांग्रेस के शोध में कर्नाटक के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से अधिक फर्जी मतदाता, अवैध पते और बड़ी संख्या में मतदाता (बल्क वोटर्स) पाए गए।

के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। राहुल का कहना है कि, शाम पांच बजे के बाद वोट टर्नआउट का बढ़ना भी हैरान करने वाला है।

महाराष्ट्र में भाजपा और चुनाव

पूरे देश में बड़े पैमाने पर 'आपराधिक धोखाधड़ी'

देशभर में चुनाव कराने की एकमात्र सांविधानिक इकाई- निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरे देश में बड़े पैमाने पर 'आपराधिक धोखाधड़ी' कर रही है। 'चुनावी धोखाधड़ी' का यह अपराध संविधान के विरुद्ध है। इसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है।

आयोग की मिलीभगत
नवंबर 2024 में कराए गए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद हमारे संदेह की पुष्टि हुई कि विधानसभा चुनाव में 'धांधली' हुई... मशीन में पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची नहीं मुहैया कराए जाने से हमें यकीन हो गया कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव में 'धांधली' के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत की है। मतदाता सूची इस देश की संपत्ति है- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा, 'महाराष्ट्र में, 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा मतदाताओं के जुड़ने से हमारा संदेह बढ़ा और फिर शाम 5 बजे

भाजपा सत्ता-विरोधी भावना से ग्रस्त नहीं- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, 'सत्ता-विरोधी भावना एक ऐसी चीज है जो हर लोकतंत्र में हर पार्टी को प्रभावित करती है। लेकिन किसी कारण से, भाजपा लोकतांत्रिक ढांचे में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मूल रूप से सत्ता-विरोधी भावना से ग्रस्त नहीं है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल एक बात कहते हैं, आपने हरियाणा चुनाव में देखा, आपने मध्य प्रदेश चुनाव में देखा और फिर अचानक परिणाम बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ पूरी तरह से अलग दिशा में चले जाते हैं। इसमें हमारा अपना आंतरिक सर्वेक्षण भी शामिल है, जो काफी परिष्कृत है।'

ऐसे 40 हजार वोटर हैं जिनके पते शून्य हैं- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने आगे कहा, 'ऐसे 40 हजार वोटर हैं जिनके पते शून्य है या फिर है ही नहीं... अलग-अलग नाम और अलग-अलग परिवार के लोग और जब हम वहां जाते हैं तो पता चलता है कि वहां कोई रहता ही नहीं है... चुनाव आयोग के मुताबिक इन पतों पर कई लोग रहते हैं लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो पता चलता है कि वहां कोई रहता



ही नहीं है... वोटर लिस्ट में कई लोगों की तस्वीरें नहीं हैं और अगर है भी तो ऐसी जिन्हें देखकर मतदाताओं की पहचान ही नहीं हो सकती।'

राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप
राहुल गांधी ने कहा, 'यह एक चुनौती है। यह सात फीट का कागज है। मान लीजिए मुझे यह पता लगाना है कि क्या आपने दो बार वोट दिया है या आपका नाम मतदाता सूची में दो बार है, तो मुझे आपकी तस्वीर लेनी होगी और फिर उसे कागज के हर टुकड़े से मिलाना होगा। यही प्रक्रिया है, और यह बहुत ही थकाऊ प्रक्रिया है। मैंने शुरू में सोचा था कि हम कई सीटों

पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब हमें इसका सामना करना पड़ा, तो हमें समझ आया कि चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता। क्योंकि वे नहीं चाहते कि हम ध्यान से देखें। इस काम में हमें छह महीने लगे... अगर चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा देता, तो हमें 30 सेकंड लगते। मैं दोहराता हूं, इसलिए हमें इस तरह का डेटा दिया जा रहा है, ताकि उसका विश्लेषण न हो... इन कागजों में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की सुविधा नहीं है। इसलिए अगर आप इन्हें स्कैन भी करते हैं, तो आप इनसे डेटा नहीं निकाल सकते। चुनाव आयोग इन कागजों की सुरक्षा क्यों कर रहा है?

संसद में एसआईआर पर व्यवधान जारी, कामकाज प्रभावित

नई दिल्ली
संसद के मानसून सत्र के लगातार 14वें दिन गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित रहा। विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा। इसके चलते कार्यवाही कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। लोकसभा में



कार्यवाही पहले 12 बजे और बाद में दो बजे तक के लिए स्थगित हुई। दो बजे कार्यवाही

प्रारंभ होने पर सरकार ने हंगामे के बीच मणिपुर माल एवं सेवाकर (संशोधन)

विधेयक, 2025 और मणिपुर बजट पारित करा लिया। इसके बाद कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी ओर राज्यसभा में सुबह हंगामे के चलते कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बजे कार्यवाही शुरू होने पर हंगामे के बीच सदन में तटीय नौवहन विधेयक, 2025 पारित किया गया। बाद में कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।

मोदी सरकार की विदेश नीति फेल: खरगे

नई दिल्ली
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगा दिए हैं। यह टैक्स भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है। इस फैसले के बाद भारत से अमेरिकी बाजार में जाने वाले सामान पर कुल 50% टैक्स लगाने लगेगा। ऐसे में भारत में इस बात को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में



नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के फैसले को केंद्र सरकार की विदेश नीति की बड़ी विफलता बताया।

खरगे ने कहा कि ट्रंप का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत की कूटनीति कमजोर और भ्रमिit नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट

से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं और अब ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं। बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने को लेकर नाराजगी जताते हुए भारत से आने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया। पहले से ही 25% टैरिफ लागू था, जिससे अब कुल शुल्क 50% हो गया है। यह आदेश 7 अगस्त से लागू हो गया है।

जस्टिस वर्मा की अपील खारिज, जांच प्रक्रिया को दी थी चुनौती

नई दिल्ली।
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जली हुई नकदी बरामद होने के मामले में जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत की पीठ जस्टिस दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं करता, इसलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र भेजा, वह असंवैधानिक नहीं था। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के



न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच पैनल को उस रिपोर्ट को अमान्य ठहराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें नकदी

बरामदगी मामले में दोषी पाया गया था। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि जांच समिति की रिपोर्ट और उसे राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को भेजना

असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को ठुकरा दिया।
जस्टिस वर्मा ने क्यों किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख, समझिए
आया जब न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से नकद राशि मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने एक इन-हाउस जांच समिति बनाई थी। इस समिति ने जांच के बाद जस्टिस वर्मा को दोषी पाया और उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई, ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके।
यशवंत वर्मा की दलीलें
मामले में जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में

दलील दी थी कि जांच में उन्हें ठीक से सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि साबित करने की जिम्मेदारी समिति पर होनी चाहिए थी, उनसे सफाई मांगना गलत था।
उनका दावा था कि निष्कर्ष पहले से तय थे और जल्दीबाजी में जांच की गई। इसपर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उनकी मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया संसद में शुरू होती है, तो वे वहां अपनी बात रख सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सीजेआई सिर्फ डाकघर नहीं है, बल्कि उनके पास अनुशासन और नैतिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी है।

कर्तव्य भवन-3 में गृह, विदेश समेत 6 से ज्यादा मंत्रालयों के होंगे दफ्तर: मनोहर लाल

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत निर्मित कर्तव्य भवन-3 के बारे में बताया कि यह भवन 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा और इसमें कुल 850 कार्यालय कक्ष होंगे। भवन में दो बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और छह मंजिलें होंगी। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई



1950 से 1970 के बीच हुआ था। इन इमारतों के रखरखाव में कठिनाइयाँ थीं। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव के. श्रीनिवास ने बताया कि यह इमारत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और आईटी-सक्षम, सुरक्षित कार्यस्थल के रूप में विकसित की गई है। इसमें आईडी कार्ड आधारित एंट्री, फ्लैप बैरियर, मेटल डिटेक्टर, बैग स्कैनर, गाड़ी स्कैनिंग सिस्टम, बूम बैरियर, वाहन

ब्लॉकर और पावर फेंसिंग जैसी उच्च सुरक्षा व्यवस्था होगी। भवन के भीतर-बाहर 700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी निगरानी 24 घंटे कंट्रोल रूम से की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन-3 को जीआरआईएचए-4 रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल निर्माण है। इसमें रूफटॉप सोलर पैनल, सोलर वॉटर हीटर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट और रिसाइकल

मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। निर्माण में मलबे का पुनः प्रयोग, हल्की दीवारों का उपयोग और ऊपरी मिट्टी के संरक्षण जैसे उपाय किए गए हैं। इससे भवन न केवल ऊर्जा कुशल होगा, बल्कि अपनी जल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पुनर्चक्रण से पूरा करेगा। इस इमारत में 600 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा एक एकीकृत कमांड एंड

कंट्रोल सेंटर पूरे सेंट्रल विस्टा की निगरानी करेगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आम नागरिकों की पहुंच आसान और सुरक्षित हो, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण है, बल्कि शासन की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और दक्षता में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी ‘एसआईआर’ : ममता बनर्जी

जेंसी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की योजना की शुरुआत भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की देन है और इसे चुनाव आयोग की मिलीभगत से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाली भाषी भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर पड़ोसी देश भेजने की कोशिश हो रही है। घाटाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंची मुख्यमंत्री ने कहा, यह (एसआईआर) केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें चुनाव आयोग को भी साथ रखा गया है। हम इससे सहमत नहीं हैं। हर किसी के लिए अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र सुरक्षित रखना संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगी, जहां वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि अगर राज्य में एसआईआर लागू हुआ तो सभी धर्मों के लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में काम करने गए बंगाल के प्रवासी मजदूरों को केवल उनकी मातृभाषा के कारण परेशान किया जा रहा है और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कुछ लोगों ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार करने की मांग की।

ईवीएम से उठा लोगों का भरोसा, चुनाव में मतपत्र प्रणाली हो लागू: केटीआर

नई दिल्ली/हैदराबाद,। तेलंगाना राज्य में विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी राम राव (केटीआर) ने कहा कि देश के लोगों में ईवीएम को लेकर कई तरह की शंकाएं हैं और लोगों का इन ईवीएम से भरोसा उठ गया है। चुनाव आयोग को मतदान के बूटेटो पर व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। केटीआर ने आज दिल्ली में मीडिया से कहा कि उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले आम चुनावों में मतपत्र प्रणाली का उपयोग कर चुनाव करने की अपील की है। केटीआर ने कहा कि मैंने पार्टी में अपनी राय व्यक्त की कि आज चुनाव आयोग के सामने छह बातें सामने आईं। उनमें से एक यह है कि भले ही अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और दुनिया के कई अन्य देशों ने कुछ समय के लिए प्रायोगिक तौर पर ईवीएम को लागू किया है, लेकिन लोगों का उन पर से विश्वास उठ गया है। अब वहां भी ईवीएम को खत्म कर मतपत्र प्रणाली लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं। ऐसे में ईवीएम से नुकसान हो रहा है। लोगों का मानना ​​है कि हमारे डाले गए वोटों की गिनती नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से ईवीएम को हटाकर मतपत्र प्रणाली लागू करने का अनुरोध किया है।

भारत बीज’ योजना से 1.4 लाख किसान लाभान्वित : अमित शाह

नई दिल्ली। देश में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, संग्रहण और वितरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना की है। यह जानकारी लोकसभा में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के प्रश्न के उत्तर में दी। शाह ने बताया कि यह समिति मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत गठित की गई है और इसका उद्देश्य ‘भारत बीज’ ब्रांड के तहत देशी प्राकृतिक बीजों का संरक्षण, उत्पादन और प्रचार-प्रसार करना है। बीबीएसएसएल का लक्ष्य देश को आयातित बीजों पर निर्भरता से मुक्त करना और किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना है। समिति के कार्यों में बीजों का उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग जैसे सभी चरण शामिल हैं। इसके अंतर्गत फाउंडेशन और सर्टिफाइड – दोनों स्तरों के बीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बीबीएसएसएल भारत सरकार की विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर कार्य करेगा और सहकारी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। इससे ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा। सहकारिता मंत्री ने आगे बताया कि बीबीएसएसएल द्वारा अब तक एक लाख 40 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इन किसानों को न केवल बेहतर किस्म के बीज प्राप्त हुए हैं, बल्कि उत्पादन में वृद्धि और उच्च कीमतों का लाभ भी मिला है। साथ ही, समिति द्वारा अर्जित लाभ में से किसानों को लाभांश देने की भी योजना है। बीबीएसएसएल का यह कदम प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे अभियानों को भी बल देता है।

एसआईआर पर संसद में चर्चा से बच रही है सरकार : गौरव गोगोई

एजेंसी नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी इंडिया ब्लाॅक ने भारी हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि यह संशोधन आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं, खासकर दलितों, पिछड़े वर्गों और गरीब समुदायों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने



संघ प्रमुख का तीन दिवसीय व्याख्यान

सौ वर्षों की यात्रा पर समाज से जुड़ने की पहल

एजेंसी नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब संघ समाज के बीच संघ, संघ कार्य, सोच और प्रेरणा लेकर आगामी एक वर्ष तक जाएगा। इसी क्रम में सरसंघाचलक मोहन भागवत अगले साल फरवरी तक देश के चार बड़े शहरों में चार प्रमुख व्याख्यान माला को संबोधित करेंगे। दिल्ली में यह व्याख्यान माला 26-28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इसमें दिल्ली और आसपास के प्रदेशों की विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों का आमंत्रित किया जाएगा।दिल्ली के केशवकुंज स्थित संघ मुख्यालय में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने पत्रकार वार्ता में इस आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्याख्यानमाला का विषय ‘100 वर्ष



पंच परिवर्तन के विषय को समाज के सामने प्रमुखता से रखेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित व्याख्यान में पहले दो दिन प्रबोधन सत्र और तीसरे दिन प्रश्नोत्तर आयोजित किए

जायेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना के 100 व्याख्यान माला बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई जैसे महानगरों में भी आयोजन होगा। दिल्ली के आयोजन के बारे में आंबेकर ने बताया कि एनसीआर व आसपास के राज्यों के प्रमुख नागरिकों को व्याख्यान में आमंत्रित किया जा रहा है। 17 प्रमुख श्रेणियों में चयनित अतिथियों की सूची तैयार की गई है, जिनमें कुल 138 उपश्रेणियाँ शामिल हैं। मीडिया से जुड़े प्रमुख लोगों, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों और विभिन्न दूतावासों से भी संवाद कर आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। पत्रकार वार्ता में मंच पर संघ के प्रांत संचालक अनिल अग्रवाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल, दिल्ली के प्रांत कार्यवाह अनिल गुप्ता एवं संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे।

ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल से दिल्ली विस अध्यक्ष की मुलाकात

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ब्रिटेन की संसद की उपाध्यक्ष नुसरत घानी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात दिल्ली विधानसभा परिसर में हुई। इस अवसर पर गुप्ता ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्य और ऐतिहासिक संबंध हमारी आधुनिक साझेदारी को दिशा देते हैं। उन्होंने भारत-ब्रिटेन संबंधों में हो रहे रणनीतिक परिवर्तन, जैसे व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीडीए) और इंडिया-यूक्रेन विजन 2035 का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश अब व्यापार,

शिक्षा, रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल व्यक्तियों में हाउस ऑफ कॉमन्स की क्लर्क असिस्टेंट सारा डेवीस, उपाध्यक्ष की निजी सचिव अबीगेल सैमुअल्स, ब्रिटिश उच्चायोग में राजनीतिक मामलों की प्रमुख नटैलिया लेह, उपप्रमुख अलेक्जेंड्रा नोएल्स, वरिष्ठ सलाहकार भावना विज और राजनीतिक सलाहकार पारुल काविया शामिल थीं। प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर विशेष चर्चा की गई। विस अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में 1.7 लाख से अधिक भारतीय छात्र

ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने गुरुग्राम में किया और 2022 में हुए शैक्षणिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता को



साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के आगामी परिसर की पहल का स्वागत

पहलों से भी प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया, जिनमें ई-विधान प्रणाली (नेवा) के माध्यम से पूरी तरह पेपरलेस कार्यप्रणाली अपनाना और 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत प्रमुख है। उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा देश की पहली नेट-जीरो कार्बन विधान सभा बन चुकी है। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि विधानसभा भवन, जो कभी ब्रिटिश इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कार्सिल का मुख्यालय था, को राष्ट्रीय विरासत के रूप में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इस दिशा में उन्होंने ब्रिटिश परियोजना से ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि इस संस्था

की गौरवमयी विरासत को सहेजा जा सके। ब्रिटेन की संसद की उपाध्यक्ष नुसरत घानी ने दिल्ली विधानसभा की मेजबानी और पहलों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि 21वीं सदी की लोकतांत्रिक और सतत शासन व्यवस्था का आदर्श भी प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने संसदों के बीच आपसी सहयोग और जनता से संवाद को और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक का समापन लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थागत सहयोग को और मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ।

शिवू सोरेन का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन, पुत्र हेमंत सोरेन ने दी मुखाग्नि

एजेंसी रामगढ़। झारखंड राज्य के प्रणेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवू सोरेन पंचतत्व में विलीन हो गए। झारखंड के जिला रामगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव नेमरा में राजकीय समान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उन्हें मुखाग्नि दी और अंतिम जोहार कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान बेहद भावुक हो गए। उनकी आंखें डबडबा गईं। बेहद भारी मन से उन्होंने अपने पिता और राजनीतिक गुरु को इस दुनिया से विदा किया। अंतिम संस्कार के दौरान उनके साथ भाई वसंत सोरेन और उनके परिवार के कई अन्य सदस्य वहां मौजूद थे। घाट पर एक ही चर्चा थी कि जिस सरजमीं से शिवू सोरेन ने संघर्ष और राजनीति शुरू की। आज उसी जगह पर पंचतत्व में विलीन हुए। सैकड़ों

गांवों से पहुंचे लोग अपने बाबा (शिवू सोरेन) और नेता को प्रणाम



कर उन्हें अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिवू सोरेन का शव लेकर जैसे ही अपने पैतृक गांव नेमरा के घाट पर पहुंचे, वहां झमाझम बारिश शुरू हो गयी।इस पर स्थानीय लोगों का कहना था कि झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले लाल को प्रकृति ने भी अंतिम विदाई दी है। गुरुजी के चाहने

वालों ने कहा कि झारखंड के लाल के निधन पर आसमान भी रो रहा है।

मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने के मामले में बंगाल के चार अधिकारी निलंबित

एजेंसी कोलकाता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने और गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया। आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने चुनावी सूची(ईआर) डाटाबेस के लॉगिन पासवर्ड अनाधिकृत लोगों के साथ साझा किए, जिसके बाद मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़े गए। यह मामला दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है।आयोग के अनुसार, निलंबित अधिकारियों में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) देबोन्मत दत्ता चौधरी और बिष्णुब सरकार के अलावा सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईईआरओ) तथागत मंडल और सुदीप दास शामिल हैं। इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी और इनके खिलाफ

एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही, आकस्मिक डेटा एंट्री



ऑपरेटर सुरोजीत हालदार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। कुछ दिन पहले भी आयोग ने पूर्वी मिदनापुर के नंदकुमार और उत्तर 24 परगना के राजारहाट-गोपालपुर क्षेत्र के दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दी थी। उन पर भी पासवर्ड डेटा एंट्री ऑपरेटरों के

साथ साझा करने का आरोप था, जिससे 102 फर्जी मतदाताओं का

संजय राउत ने उत्तरकाशी त्रासदी पर जताया दुख, बोले- सरकार को पहाड़ी राज्यों पर देना होगा विशेष ध्यान

एजेंसी मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बुधवार को उत्तराखंड में बादल फटने की घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देशभर से पर्यटक पहाड़ी राज्यों में जाते हैं। लोग वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर आते हैं, इसलिए उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने प्रेसवालों को संबोधित करते हुए बताया कि महाराष्ट्र के सैकड़ों पर्यटक और लोग पहाड़ी इलाकों में बाढ़ के कारण फंस गए हैं, जिससे पूरा देश चिंतित है। उन्होंने मांग की कि इन क्षेत्रों में मजबूत इंतजाम करने होंगे ताकि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही, संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भी निशाना साधा और कहा कि ट्रंप ने

भारत को व्यापार के लिए अच्छे साथी नहीं बताया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं है, तो बिना व्यापार के इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? क्या ट्रंप पीएम मोदी को झूठ बता रहे हैं? ट्रंप बार-बार पीएम को अपमानित कर रहे हैं, जिससे दुनिया में प्रधानमंत्री

मोदी के खिलाफ माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सय समझना चाहिए। इसके अलावा, संजय राउत ने इंडिया ब्लाॅक की बैठक पर भी बात की और कहा कि गठबंधन की लंबे समय बाद होने वाली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे देश की मौजूदा स्थिति, पीएम मोदी के दावों की सच्चाई, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार चुनाव।

पारंगत है। उसने अतुल के नाम से फर्जी कंपनी बनवायी ताकि वर्तमान खाता खोला जा सके। कौशल कुमार ने साइबर अपराधियों को ऐसे कई फर्जी खाते और किट उपलब्ध कराए। उसने मोहन गार्डन में किराए पर ऑफिस लेकर खाता खोलने का पूरा धंधा शुरू किया था।

सफलता-असफलता के बीच का संतुलन, प्रयास

हम देखेंगे... लाजिम है कि हम भी देखेंगे... मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने ये नज्म साढ़े चार दशक पहले तब लिखी थी जब पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक ने हुकूमत की बागडोर संभाली थी। लेकिन इस नज्म को लोकप्रियता हासिल हुई 1986 में इकबाल बानो के जरिए। दरअसल, जिया-उल-हक की सरकार ने साड़ी को गैर इस्लामिक बताकर उस पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में इकबाल बानो ने सफेद साड़ी पहनकर एक बड़े जनसमूह के सामने यह नज्म गायी थी। इसकी एक पंक्ति 'सब ताज उछाले जायेंगे, सब तख्त गिराए जायेंगे' गाते ही भीड़ ने 'इंकलाब जिंदाबाद' नारे लगाने शुरू कर दिये। उसी वक़्त से यह नज्म सरकार और उसके तंत्र के प्रति असंतोष व्यक्त करने, प्रतिकार करने का माध्यम बन गई। भारत में भी जनवादी-प्रगतिशील संगठनों और जन आंदोलनों ने इसे हाथों-हाथ ले लिया और इस नज्म ने जनगीत की शक्ल अख़्तियार कर ली।

बरसों-बरस यह नज्म जलसों-जुलूसों, धरने-प्रदर्शनों, बैठकों-सभाओं में गायी जाती रही। सरकारें आती-जाती रहीं, इस रचना में किसी को कोई बुराई नजर नहीं आई। लेकिन फिर 2019 आया जब बाकी देश की तरह आईआईटी कानपुर के छात्र नागरिकता संशोधन कानून (सीएए-एनआरसी) के विरोध में इकट्ठा हुए और यह नज्म गायी। दूसरे पक्ष के कुछ छात्रों ने इस नज्म को हिन्दू विरोधी बताते हुए बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने संस्थान के निदेशक को शिकायत की कि यह नज्म से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। इस पर संस्थान ने एक जाँच समिति का गठन कर दिया। समिति ने अपनी जांच में पाया कि फैज की यह नज्म हिंदू विरोधी नहीं, बल्कि सत्ता के विरोध का प्रतीक है। हालांकि यह तथ्य, साहित्य की सामान्य समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था।

लेकिन जब किसी विचारधारा के प्रति विद्वेष सामान्य बुद्धि पर हावी हो जाये तो कानपुर की घटना का दोहराव होना ही होता है। हाल ही में यह हुआ भी। 2015 की अत्यधिक चर्चित और पुरस्कृत मराठी फिल्म 'कोर्ट' के अभिनेता वीरा साथीदार की स्मृति में नामपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीरा एक लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 2021 में महज 61 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। फिल्म 'कोर्ट' में उन्होंने नारायण कांबले का किर्दार निभाया था। इस फिल्म ने दुनियापर में लगभग 60 करोड़ की कमाई की थी। वीरा के स्मृति आयोजन में 'हम देखेंगे...' नज्म गायी गयी। किसी दक्षिणपंथी संगठन के सदस्य ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। पुलिस ने भी आनन-फानन में मामला दर्ज कर लिया। उसने स्व. साथीदार की पत्नी पुष्पा समेत अन्य के खिलाफ देश की एकता-अखंडता को नुकसान पहुंचाने, धार्मिक भावना भड़काने और अशांति फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

शिकायत में कहा गया है कि फैज की कविता में 'सिंहासन हिलाने' और 'तानाशाही के दौर' जैसी बातें कही गई हैं। यही भी ऐसे समय में जब पहलगाम ह्रादसे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। अब यह कोई लाल बुलबुलकड़ ही बता सकता है कि सालों से गायी जा रही एक नज्म या कविता का दो देशों के बीच उभजे तनाव से क्या वास्ता हो सकता है- खासतौर से तब, जब वह नज्म किसी देश, समाज या धर्म के विरोध में नहीं, बल्कि तानाशाही और अन्याय के विरुद्ध लिखी गई हो। यहां ये बातना लाजिमी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता भी फैज अहमद फैज के प्रशंसक थे और जिस नज्म पर इस वक़्त सवाल खड़े किये जा रहे हैं, वह भी अटल जी को बेहद पसंद थी। लेकिन न जाने क्यों दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और मजबूती का दावा करने वाली उसकी सरकार को अपने इस पुरखे के आचरण-व्यवहार से सबक लेना चाहिये।

फैज की बात चली है तो यह बातना जरूरी है कि 2022 में सीबीएसई ने 10वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान की किताब से उनकी कुछ कविताएं और लोकतंत्र से संबंधित अध्याय हटा दिये थे। इधर हाल ही में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रो. अली खान महमूदाबाद को सोशल मीडिया पर उनकी एक पोस्ट के बहाने गिरफ्तार किया गया, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। प्रो. खान के खिलाफ शिकायत करने वाली हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया एक खबरिया चैनल की एंकर के छः बार पूछने पर भी बता नहीं पाई कि आखिर उस पोस्ट में कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य आपत्तिजनक था। इन्हीं मोहतरमा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे राम रहीम को बलात्कारी कहने से बचती नजर आ रही हैं। रेनू भाटिया की तरह भाजपा का कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं बता पा रहा है कि जब कर्नल सोफिया कुरेशी और भारतीय सेना के बारे में अनर्गल बयान देने वाले मंत्रियों को बचाने की सारी कोशिशें की जा रही है, तब प्रो. महमूदाबाद और पुष्पा साथीदार पर कार्रवाई क्यों की गई। क्या सिर्फ इसलिए कि दोनों में से एक मुसलमान है और दूसरा अंबेडकरवादी। यह याद रखा जाना चाहिये कि हिन्दुस्तान हमेशा से उदार प्रवृत्तियों वाला देश रहा है और यहां असहमतियों-आलोचनाओं का सम्मान होते आया है। सरकार से अलग राय रखने और सवाल पूछने वालों पर बेजा कार्रवाई कर जनता को डराने की कोशिश ही न की जाये तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। वरना एक न एक दिन यह डर खत्म हो जायेगा। और तब क्या होगा - हम देखेंगे...

आंखों से बार-बार पानी आना किस बीमारी का लक्षण है?

आंखों से बार बार पानी आना कई बीमारियों का लक्षण होता है. कई बार यह बीमारी गंभीर भी हो सकती है. यदि आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं तो आपको ड्राई आई की समस्या हो सकती है. ड्राई आई होने पर बार बार पानी आता है. यदि ऐसा नहीं है तो आपको इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए. आंखों में बार बार पानी आना किस बीमारी के लक्षण है. इस बारे में हमने बात की सीनियर आई सर्जन से। अक्सर हमारी आंखों से बिना कारण पानी निकलने लगता है. यह आंखों की गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है. आंखों में ड्राइनेस या धूल और बाल जाने के कारण भी ऐसा हो सकता है. कई बार धूल के कण ऐसे स्थान पर होते हैं जिनके कारण आंखों में खुजली या असहजता नहीं होती, लेकिन आंखों का सिस्टम उसे बाहर निकालने के लिए पानी का सहारा लेता है. इसके अलावा कई बीमारियां भी हैं जिनके कारण बार बार आंखों से पानी आता है.

इन बीमारियों में आता है आंखों में बार बार पानी

एमएफजी अस्पताल के सीनियर आई सर्जन डॉ. नरेंद्र कुमार बताते हैं कि बिना कारण आंखों से पानी आना आंशुओं की ग्रंथि की समस्या का लक्षण होता है. आंसू की नलिका में किसी तरह का अवरोध होता है तो बार बार आंखों में पानी आता है.इसके अलावा यदि पलकों में किसी तरह की समस्या है तब भी आंखों में पानी आता है. पलकों का बाहर या अंदर ओर मुड़ने के कारण भी ऐसा होता है. इसके अलावा बेल्स पाल्सी के कारण भी ऐसा होता है. बेल्स पाल्सी एक तंत्रिका संबंधी विकार है. इसमें चेहरे की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं. जिससे आंखें बंद होने या पलकें ठीक से बंद न होने की समस्या हो सकती है. जिसके कारण बार बार आंख से पानी आता है. डॉ. नरेंद्र कुमार कहते हैं कि यदि आंखों से बार बार पानी आ रहा है तो आपको डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए. इसके लिए घरेलू नुस्खे या लापरवाही आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

माता-पिता और संतान के संबंधों की संस्कृति को जीवंतता दें

- ललित गर्ग -

विश्व के अधिकतर देशों की संस्कृति में माता-पिता का रिश्ता सबसे बड़ा एवं प्रगाढ़ माना गया है। भाग्त में तो इन्हें ईश्वर का रूप माना गया है। माता-पिता को उनके बच्चों के लिए किए गए उनके काम, बच्चों के प्रति उनकी निस्वार्थ प्रतिबद्धता और इस रिश्ते को पोषित करने के लिए उनके अजीबान त्याग के लिए सम्मान और सराहना देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व माता-पिता (अभिभावक) दिवस 1 जून को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का पालन दिवस है। यह दिन हमें परिवारों के विकास में माता-पिता और उनके जैसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। 2025 के लिए थीम है ह्रमाता-पिता का पालन-पोषणह्म। यह थीम माता-पिता के रूप में पालन-पोषण को एक महत्वपूर्ण कोशल के रूप में मान्यता देती है और हमें माता-पिता के रूप में बच्चों के विकास और कल्याण के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। अधिकांश देशों में सदियों से माता-पिता का सम्मान करने की परंपरा रही है। माता-पिता ईश्वर का सबसे अच्छा उपहार हैं। जीवन में कोई भी माता-पिता की जगह नहीं ले सकता। वे सच्चे शुभचिंतक हैं।

माता-पिता ही बच्चों की सुरक्षा, विकास व समृद्धि के बारे में सोचते हैं। बावजूद बच्चों द्वारा माता-पिता की लगातार उपेक्षा, दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना की स्थितियों बढ़ती जा रही है, जिन पर नियंत्रण के लिये यह दिवस मनाया जाता है। भारत में जहां कभी संतानें पिता के चेहरे में भगवान और मां के चरणों में स्वर्ग देखती थीं, आज उसी देश में संतानों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण बड़ी संख्या में बुजुर्ग माता-पिता की स्थिति दयनीय होकर रह



गई है। इस दिवस को मनाने की सार्थकता तभी है जब हम केवल भारत में ही नहीं है बल्कि विश्व में अभिभावकों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने की भी है। प्रश्न है कि दुनिया में अभिभावक दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों अभिभावकों की उपेक्षा एवं प्रताड़ना की स्थितियां बनी हुई है? चिन्तन का महत्वपूर्ण पक्ष है कि अभिभावकों की उपेक्षा के इस गलत प्रवाह को कैसे रोके। क्योंकि सोच के गलत प्रवाह ने न केवल अभिभावकों का जीवन दुश्वार कर दिया है बल्कि आदमी-आदमी के बीच के भावात्मक फासलों को भी बढ़ा दिया है। विचारणीय है कि अगर आज हम माता-पिता का अपमान करते हैं, तो कल हमें भी अपमान सहना होगा। समाज का एक सच यह है कि जो आज जवान है उसे कल माता-पिता भी होना होगा और इस सच से कोई नहीं बच सकता। हमें समझना चाहिए कि

माता-पिता परिवार एवं समाज की अमूल्य खिरासत होते हैं। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए 2007 में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण विधेयक संसद में पारित किया गया है। इसमें माता-पिता के भरण-पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के पारित किया गया है। इसमें माता-पिता के भरण-पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। आज के माता-पिता समाज-परिवार से कटे रहते हैं और सामान्यतः इस बात से सर्वाधिक दुःखी है कि जीवन का विशाद अनुभव होने के बावजूद कोई विवश है। माता-पिता को इस दुःख और कष्ट से छुटकारा जरूरत है। सीमा तक, कितना, किस रूप में और कितनी बार होता है तथा इसके पीछे कारण

आज्ञा से भगवान श्रीराम जैसे अवतारी पुरुषों ने राजपाट त्याग कर वनों में विचरण किया, मातृ-पितृ भक्त श्रवण कुमार ने अपने अन्धे माता-पिता को काँवड़ में बैठाकर चारधाम की यात्रा कराई। फिर क्यों आधुनिक समाज में माता-पिता और उनकी संतान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। और न ही उनकी राय को महत्व देता है। समाज में अपनी एक तरह से अहमियत न समझे जाने के कारण हमारे माता-पिता दुःखी, उपेक्षित एवं त्रासद जीवन जीने को विवश हैं। माता-पिता को इस दुःख और कष्ट से छुटकारा जरूरत है। सीमा तक, कितना, किस रूप में और कितनी बार होता है तथा इसके पीछे कारण

हम नहीं देख पाए, वो अब भी गा रहे थे

ट्रम्प को नहीं मिली कोई सफलता

- अंजन गोंय

अपने घोषित लक्ष्यों की किसी भी स्पष्ट उपलब्धि से वंचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार-बार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को अपने श्रेय के रूप में लिया। उन्होंने बार-बार दावा किया कि यह उनके 'व्यापार के उपयोग के कारण था जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष विराम हुआ'। इस दावे को भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बार-बार खारिज किया है।

इस साल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रम्प ने दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, तब से एक सी तीस दिन बीत चुके हैं। शुरूआती दिनों में बड़ी उम्मीदें जगाने के बाद, अति सक्रिय राष्ट्रपति अब धीरे-धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि वे एक बड़ी विफलता हैं। 'ट्रम्प हमेशा पीछे हटते हैं।' यह एक ऐसा लेबल है जिसे चीनी नेटिजेंस ने उनके लिए गढ़ा था क्योंकि वे टैरिफ पर चीन के साथ लड़ाई से डरते थे। ट्रम्प ने चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को 145प्रतिशत तक बढ़ा दिया था और बातचीत शुरू होने से पहले ही चरणों में इसे 30प्रतिशत तक कम कर दिया था। चीनियों ने ट्रम्प की रियायतों को टैरिफ युद्ध में चीन के साथ उलझने के उनके डर के रूप में वर्णित किया। इसके तुरंत बाद प्रसिद्ध वॉल स्ट्रीट में उनके अपने देशवासियों ने उन्हें 'टैको(ट्रम्प ऑलवैचिकन्स आऊट) ट्रेड' की उगाधि दी, जिसका संदर्भ टैरिफ पर उनके तेजी से बदलते रुख के आधार पर अमेरिकी शेयर बाजारों में होने वाले उतार-चढ़ाव से था।

जब एक रिपोर्टर ने ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, तो वह स्पष्ट रूप से गलत ढंग से पेश आये। उन्होंने इसे 'सबसे ख़तरा सवाल' बताया और उसे फिर कभी स्रेस न उठाने के लिए कहा। उन्हें यह साबित करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी कि वे कायर नहीं हैं। लेकिन अब सर्वव्यापी बैज का खंडन करने के उनके प्रयासों से, ट्रम्प अब एक मुखर व्यक्ति साबित हुए हैं, जो अपने वायदों के लायक नहीं हैं और वे जिन मुद्दों को उठा रहे थे, उन पर सख्त रुख अपनाते की बात कर रहे हैं। चाहे वह यह दावा हो कि वे सत्ता में आने पर एक दिन में यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे। या फिर अमेरिकी संघीय खर्च और बजट घाटे को कम करने के उनके दावे हों- सभी मामलों में, ट्रम्प को धोखेबाज कहा गया है।ट्रम्प के सबसे करीबी सहयोगी, एलन मस्क, जिन्हें उन्होंने सरकारी दक्षता के लिए विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था - तथाकथित डोज (डिफाटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर) - ने बुधवार को अपने कदम पीछे खींच लिए और वास्तव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संघीय खर्च में कटौती करने में ट्रम्प की विफलता को सार्वजनिक रूप से आलोचना की। वास्तव में, मस्क को एक टीवी साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से यह कहते हुए सुना गया था कि सैन्य और रक्षा में संघीय खर्च में भारी कर कटौती और बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी देने के लिए बहुचर्चित 'बड़ा और सुंदर' विधेयक वास्तव में डोनाल्ड ट्रम्प के पहले के वायदों से मुकरना था। इस विधेयक से अमेरिकी संघीय घाटे में 3.8 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होगी। यह उनके द्वारा वायदा किये गये कमी लाने के स्थान पर अमेरिकी सरकार के घाटे में एक बहुत बड़ी उछाल है। मस्क ने विडंबनापूर्ण रूप से बताया है कि यह विधेयक या तो बड़ा हो सकता है या सुंदर, यह दोनों नहीं हो सकता, जो ट्रम्प के वर्णन के बिल्कुल विपरीत है। मस्क वस्तुतः यह कह रहे हैं कि ट्रम्प अमेरिकी राजकोषीय उलझन के अपने वायदे किये गये बड़े टिकट सुधारों से पीछे हट रहे हैं। शंक्सपियर के शब्दों का उपयोग करते हुए, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए उन्होंने कहा यह सबसे निश्ची कटौती है।

ट्रंप ने कहा-अमेरिका के लिए भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं

एजेंसी
वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने कहा कि भारत का शुल्क (टैरिफ) बहुत ज्यादा है। इसलिए अमेरिका उसके साथ कम व्यापार करता है। उन्होंने कहा कि इसलिए अमेरिका के लिए भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। द व्हाइट हाउस ने अपने समाचार प्रभाग में सीएनबीसी को दिए राष्ट्रपति ट्रंप के साक्षात्कार के मुख्य अंश पांच अगस्त को प्रसारित किए हैं। इनमें यह बात कही गई है। ट्रंप ने कहा कि भारत हमारे साथ बड़ा व्यापार करता है। अमेरिका उस अनुपात में भारत के साथ काफी कम व्यापार करता है। उन्होंने कहा, इसलिए मैं 25 फीसद टैरिफ पर सहमत हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटों में इसे काफी बढ़ा दूंगा। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। यही नहीं भारत युद्धक विमानों को ईंधन दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीएनबीसी के स्कॉक बॉक्स में अपने दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए अपनी प्रार्थमिकताएं भी गिनाईं। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ संबंधों पर कहा, यदि हम कोई समझौता कर लेते हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि मैं वर्ष के अंत से पहले चीन के साथ बैठक करूंगा। वैसे भी हम समझौते के बहुत करीब पहुंच रहे हैं।

टैरिफ नीति पर ट्रंप को निक्की हेली की सलाह- भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते न बिगाड़ें

वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से रिश्ते न बिगाड़ने की सलाह दी है।पूर्व राजदूत हेली ने कहा है कि भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ से भारत-अमेरिकी संबंधों में खटास आ सकती है।इससे पहले ट्रंप ने एकबार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अगले 24 घंटों में भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे।हालांकि ट्रंप ने भारत की तरफ से दिए गए उस तथ्य को जानकारी न होने की बात कही, जिसमें भारत ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं। टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका तनाव पर भारतीय मूल की पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अहम सलाह देते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता में खटास आने का जोखिम है उन्होंने ट्रंप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए एक्स पोस्ट में लिखा- भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए लेकिन रूस व ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन को 90 दिनों की टैरिफ छूट मिल गई।भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते बिगाड़ कर चीन को छूट न दें।

इजराइल की गाजा में पूर्ण सैन्य नियंत्रण की योजना पर विचार, सैन्य और जनमत से टकराव

तेल अवीव। इजराइल सरकार गाजा पट्टी के उस 2.5 प्रतिशत क्षेत्र में भी सेना तैनात करने पर विचार कर रही है, जो अभी उसके नियंत्रण में नहीं है। हालांकि इस संभावित कदम को लेकर सैन्य नेतृत्व और देश की अधिकांश जनता में चिंता जताई जा रही है कि इससे हमास के कब्जे में बचे बंधकों की रिहाई की संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं। एक वरिष्ठ इजराइली अधिकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू इस निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक इसी सप्ताह बुला सकते हैं। नेतन्याहू ने तीन घंटे लंबी सुरक्षा बैठक की, जिसमें आईडीएफ (इजराइल डिफेंस फोर्स) के चीफ ऑफ स्टॉफ एयाल जालिर ने सैन्य विकल्पों की प्रस्तुति दी। आईडीएफ ने साफ किया है कि सुरक्षा कैबिनेट द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए वह तैयार है। गाजा में जारी लगभग दो वर्ष लंबे युद्ध को लेकर इजराइल पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि खाद्य आपूर्ति पर इजराइली प्रतिबंध और युद्ध से हुई तबाही के कारण गाजा में भुखमरी का खतरा बढ़ रहा है। जुलाई के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र और एनजीओ के माध्यम से मानवीय सहायता के वितरण को आसान बनाने का वादा किया था। सरकार ने खाद्य और स्वच्छता सामग्री की वार्षिकपूर्व पहुंच में कुछ और ढील देने की घोषणा की, लेकिन यह कड़ी सुरक्षा जांच के अधीन रहेगी।

मोल्डोवा में चुनावी धोखाधड़ी पर रूस समर्थक क्षेत्रीय नेता को 7 साल की सजा

किशिनाव। मोल्डोवा की एक अदालत ने दक्षिणी क्षेत्र गागाज़िया की नेता और रूस समर्थक राजनेता येवगेनिया गुटुल को चुनावी धोखाधड़ी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश में आगामी 28 सितंबर को महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। गुटुल पर आरोप था कि उन्होंने 2019 से 2022 के बीच रूस से अवैध फंडिंग के जरिए मोल्डोवा में एक राजनीतिक दल को आर्थिक सहायता पहुंचाई। यह पार्टी ईलान शोर द्वारा स्थापित की गई थी, जो स्वयं मोल्डोवा में धोखाधड़ी के दोषी करार दिए जा चुके हैं और फिलहाल रूस में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। गुटुल, जो शोर की अब प्रतिबंधित पार्टी की पूर्व सचिव थीं रही हैं, 2023 में गागाज़िया की गवर्नर चुनी गईं। उस चुनाव पर भी चोट खरीद के आरोप लगे थे। यूरोपीय संघ ने उन्हें मोल्डोवा में 'जननीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंधित कर रखा है। गुटुल ने अदालत के इस फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए अपील करने की घोषणा की है।

कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, सैकड़ों इमारतों पर मंडरा रहा खतरा

एजेंसी
लॉस एंजिल्स । मध्य कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग ने अब तक 82,000 एकड़ (लगभग 332 वर्ग किलोमीटर) से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में लिया है। यह आग पिछले पांच दिनों से भयानक रूप ले चुकी है और सैकड़ों इमारतों को खतरा बना हुआ है। अमेरिकी वन सेवा और कैलिफोर्निया के वाकियों व अग्नि सुरक्षा विभाग के अनुसार, 'गिफोर्ड फायर' नाम की यह जंगल की आग शुक्रवार दोपहर उस समय धड़क उठी, जब कैलिफोर्निया हाईवे के पास चार अलग-अलग जगहों पर आग लगा गई और उन्होंने मिलकर एक विकराल आग का रूख धारण कर लिया। यह आग अब सैन लुइस ओबिस्पो और सांता बारबरा काउंटी में फैल चुकी है।



चपेट में आने से 870 से ज्यादा इमारतें खतरे में हैं। मंगलवार सुबह तक इस आग पर सिर्फ 7 प्रतिशत ही काबू पाया जा सका है। आग की वजह से सांता बारबरा और सैन लुइस ओबिस्पो के लोगों को अपने घर

छह सदस्यों वाले परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं। अफगान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज़ ने रहमान के हवाले से कहा, हम अब अपने देश लौट आए हैं। हम ईरान में कृषि संबंधी कार्य करते थे। अगर यहाँ कृषि क्षेत्र में अवसर मिलता है, तो मुझे खुशी होगी।

एक अन्य अफगान प्रवासी ने कहा, अगर ईरान में हमने जो काम किया, वह हमारे देश में उपलब्ध होता, तो हम कभी लोग नहीं जाते। ईरानी सरकार और वहाँ के लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। हमने वहाँ घर किएए पर लिए, और वे हमें हमारी मजदूरी नहीं देते।- हाल ही में,

बांग्लादेश में यूनुस सरकार की कार्रवाई तेज, अवामी लीग के 1,593 नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार

एजेंसी
ढाका। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई के तहत बांग्लादेश पुलिस ने अब तक देशभर से 1,593 अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में दी गई। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने भी राजधानी के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 11 अवामी लीग कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार में लिया है। डीएमपी के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद तालेबुर रहमान ने इसकी पुष्टि की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अवामी लीग समर्थक और प्रसिद्ध ब्लॉगर कमाल पासा चौधरी भी शामिल हैं। बांग्लादेश के प्रमुख बांग्ला अखबार ने इस बात की जानकारी दी है।

कमाल पासा चौधरी की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए, अवामी लीग के नेता और पूर्व राज्य सूचना एवं प्रसारण मंत्री मोहम्मद आराफत गया है। यह यूनुस के तानाशाही शासन में प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष आवाजों को दबाने की एक और कोशिश है। आराफत के अनुसार,



ने इसे अन्यायपूर्ण करार दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुक्ति संग्राम समर्थक कमाल पासा चौधरी को अन्यायपूर्ण रूप से गिरफ्तार किया गया है। यह यूनुस के तानाशाही शासन में प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष आवाजों को दबाने की एक और कोशिश है। आराफत के अनुसार,

बाइडेन के नेतृत्व में रूस-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व गिरावट आई थी : क्रेमलिन

एजेंसी
मास्को। मास्को ने बुधवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब तक कोई बैठक न होने पर उसे कोई हैरानी नहीं है। क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान रूस-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व गिरावट आई थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इस बात पर जोर दिया कि रूस के आधुनिक इतिहास में पहली बार है जब नए अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के छह महीने से ज्यादा समय बाद भी अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है। पहले, रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन का इंतज़ार आमतौर पर एक से पांच महीने तक होता था। लेकिन इस बार, ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के छह महीने और 16 दिन बीत चुके हैं। हालांकि, रूसी सरकारी

समाचार एजेंसी टीएएसएस के रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति और पुतिन के बीच कोई व्यक्तिगत प्रतिबंधों की समयसीमा को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव



मुलाकात नहीं हुई है। पेसकोव ने कहा, किसी अनोखी स्थिति के बारे में बात करना असंभव है। आखिरकार, पिछले (अमेरिकी) प्रशासन के तहत, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में अभूतपूर्व गिरावट आई थी। उन्होंने कहा कि बाइडेन के नेतृत्व में, मास्को और वाशिंगटन के बीच अभूतपूर्व संख्या में परेशान करने वाली चीजें इकट्ठी हो गईं। अमेरिकी

वित्तीय बुधवार को रूसी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए मास्को में होंगे। वित्तीय की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है।ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि अगर यूक्रेन संकट के समाधान पर कोई समझौता नहीं हुआ, तो 9 अगस्त तक रूस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

टीटीपी का खैबर कबायली जिले की अशांत तिराह घाटी के आदिवासियों से समझौता

एजेंसी
इस्लामाबाद। प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने इस बात पर सहमति जताई कि वह सुरक्षा बलों के खिलाफ अपने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों को मानव डाल के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। टीटीपी नेताओं ने यह भी वादा किया कि अब से खैबर कबायली जिले की अशांत तिराह घाटी में जकात और उशर के नाम पर किसी से जबरन वसूली नहीं की जाएगी। डान अखबार की खबर के अनुसार टीटीपी के लेंटरहेड पर पश्तो भाषा में लिखे और उसकी सर्वोच्च परिषद (रहबारी शूर) की मुहर लगे इस समझौते को बार कंकरखेल के एक बुजुर्ग ने स्थानीय आदिवासियों के सामने पढ़ा। यह समझौता आम आदिवासियों के खिलाफ शरुता समाप्त करने और

शांति बहाल करने के लिए तिराह से वापसी की उनकी मांग के जवाब में किया गया है। खैबर के तिराह में बार



कंकरखेल जनजाति के जिरगा के दौरान यह समझौता हुआ।

इस दौरान प्रतिबंधित टीटीपी नेताओं ने सुरक्षा बलों के खिलाफ अपना सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखने

और उन लोगों को सजा देने की कसम खाई, जिन्होंने सुरक्षा बलों का समर्थन किया या उनके खिलाफ

है।हम स्थानीय लोगों के आंतरिक और निजी मामलों में अपनी भागीदारी को अनुचित मानते हैं और इसलिए हमने अपने स्वयंसेवकों को ऐसा करने से सख्त निषेध किया है। समझौते में स्पष्ट किया गया है कि टीटीपी सदस्य लोगों के घरों में शरण नहीं लेंगे या सुरक्षा बलों के खिलाफ बंकर के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वे ऐसी किसी भी निजी इमारत में सुरक्षा बलों के रुकने का विरोध करेंगे। टीटीपी नेताओं ने यह भी सहमति व्यक्त की कि लड़ाके किसी का अपहरण या उन्नीड़न नहीं करेंगे। तिराह के बार कंकरखेल में बातचीत का पहला दौर 28 जुलाई को हुआ था। इस दौरान टीटीपी के स्थानीय कमांडरों ने अफगानिस्तान में अपने नेतृत्व को जिरगा की मांगों से अवगत कराने के लिए पांच अगस्त तक का समय मांगा था।

अमेरिकी विदेश विभाग ने ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी से किया इनकार

एजेंसी
न्यूयॉर्क । अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने भारत की उन प्रतिक्रियाओं पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, जिनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। एक पत्रकार द्वारा विदेश मंत्री एस. जयशंकर की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, 'मैं किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर कोई राय नहीं दूंगी कि वे क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। उन्होंने व्यवसायिक लहजे में कहा, 'मैं तो मुश्किल से यहां भी ऐसा कर पाती हूँ। उन्होंने थोड़ी हैरानी जताते हुए कहा, 'मैं तो मुश्किल से यहां भी ऐसा कर पाती हूँ। लेकिन उन्होंने भारत द्वारा तेल खरीद की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप ही 'मार्गदर्शक' हैं, और रूस जो कर रहा है और वे देश जो यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध में मदद कर रहे हैं, तो यह राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करेगा कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ट्रंप के बयान के बाद आयोजित नियमित ब्रीफिंग में ब्रूस ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा

की थी कि वह रूस से तेल खरीदने और उससे बने उत्पादों को फिर से बेचने पर भारत पर 24 घंटे के भीतर 25 प्रतिशत से अधिक का भारी शुल्क लगाएंगे।उन्होंने आरोप लगाया, वे रूसी तेल खरीद रहे हैं और रूसी युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को टैरिफ के खतरे की अप्रत्यक्ष आलोचना करते हुए कहा हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था देखना है, न कि कुछ लोगों के प्रभुत्व वाली। हालांकि जयशंकर ने अपने बयान में ट्रंप का जिक्र नहीं किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और अफगान अफगानिस्तान लौटे हैं। 2005 तक ईरान और पाकिस्तान से 21 लाख से ज्यादा अफगान वापस आ चुके हैं। अफगानिस्तान की स्थिति बेहद कमजोर है। उसे इस वर्ष के लिए आवश्यक 478 मिलियन डॉलर का केवल 24 प्रतिशत ही मिल पाया है।

ईरान और पाकिस्तान से निर्वासित कई अफगान प्रवासियों ने आश्रय, बेरोजगारी और बुनियादी सेवाओं की कमी के कारण अपने देश में कठिन जीवन स्थितियों के बारे में चिंता जताई है।

बीएलए ने बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली, हमले में पाकिस्तान की सेना के मेजर समेत तीन सैन्यकर्मियों को मार गिराने का दावा

एजेंसी
इस्लामाबाद। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बलूचिस्तान के नुश्की जिले में हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसके हमले पाकिस्तान की सेना के एक मेजर समेत तीन सैन्यकर्मियों मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए। बीएलए ने दावा किया कि उसकी खुफिया शाखा जिराब की पुख्ता सूचना पर मेजर के काफिले को निशाना बनाया गया।

द बलूचिस्तान पोस्ट ने बीएलए प्रवक्ता जयिंद बलूच के हवाले से यह खबर प्रसारित की है। यह हमला रात करीब 8:00 बजे नुश्की जिले के गरगिना इलाके में एक सड़क किनारे लगे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से एक बुलेटप्रूफ सैन्य वाहन को निशाना बनाकर किया गया। मृतकों की

पहचान मेजर रिजवान, नायब सुबेदार अमीन और लॉस नायक यूनिट के रूप में होने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की सेना ने अभी



तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। बीएलए प्रवक्ता जयिंद बलूच ने दावा किया कि लड़कों ने जिराब की सूचना के आधार पर मेजर रिजवान के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी लेती है।

बीवाईसी ने बलूचिस्तान में संघीय सरकार के चेहल्लुम यात्रा मार्ग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की आलोचना की

एजेंसी
क़ट्टा। बलूचिस्तान के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की वकालत करने वाले समूह बलूच यकजहेती समिति (बीवाईसी) ने संघीय सरकार के हाल ही में बलूचिस्तान से होकर चेहल्लुम के लिए इराक जाने वाले शिया तीर्थयात्रियों के काफिले पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की निंदा की है। समूह ने इस कदम को संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघनऔर इसे तथाकथित सुरक्षा के नाम पर किया गया धार्मिक भेदभाव बताया है। बीवाईसी की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी के बाद आई है। आसिफ ने इस्लामाबाद में कहा था कि सरकार ने तीर्थयात्रियों के काफिले को निशाना बनाकर आतंकवादी हमलों के खतरे के कारण क़ट्टा से 800 किलोमीटर के भूमि मार्ग पर यात्रा

प्रतिबंधित कर दी है। द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, बीवाईसी ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।



तथाकथित सुरक्षा के नाम पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अस्वीकार्य है। समूह ने आरोप लगाया कि राज्य ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने मूल कर्तव्य को पूरा करने के बजाय यह प्रतिबंध लगाया है। बीवाईसी ने कहा, राज्य की जिम्मेदारी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग

प्रदान करना है, न कि आस्था के आधार पर उन्हें बाधित करना। बीवाईसी ने बयान में कहा कि शिया तीर्थयात्रियों ने प्रतिबंध के विरोध में कराची से रिमदान सीमा तक लंबे मार्च की घोषणा की है। समूह ने इस मार्च को संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार बताया और विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों के साथ अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की।बीवाईसी ने कहा, हम मांग करते हैं कि शिया तीर्थयात्रियों के कारवां पर प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए और बलूचिस्तान से ईरान और इराक जाने वालों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। बयान में अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वे बल प्रयोग या दबाव के जरिए मार्च में बाधा डालने का प्रयास न करें। गौरतलब है कि पाकिस्तान के संघीय गृहमंत्री ने भी हाल ही में घोषणा की थी कि शिया तीर्थयात्रियों को बलूचिस्तान के रास्ते इराक जाने से रोका जाएगा।

अमेरिकी न्याय विभाग को जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलें सौंपने के लिए समन

एजेंसी
वाशिंगटन। हाउस ओवरसाइट कमेटी अध्यक्ष जेम्स कॉमर ने अमेरिकी न्याय विभाग को समन जारी किया। विभाग से कहा गया है कि वह नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोपित जेफरी एपस्टीन से जुड़ी पूरी फाइलें सौंप दे। कॉमर ने दूसरा समन पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन की गवर्नी के लिए जारी किया गया है। कॉमर ने कहा कि वह चाहते हैं कि न्याय विभाग 19 अगस्त तक या उससे पहले पूरी फाइलें सौंप दे। एबीसी न्यूज़ के अनुसार, कॉमर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि विभाग एपस्टीन की मैक्सवेल के मामलों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी को सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहा है। यह आवश्यक है कि कांग्रेस संघीय सरकार यौन तस्करी कानूनों के प्रवर्तन और विशेष रूप से एपस्टीन और मैक्सवेल की जांच और अभियोजन के संचालन

की निगरानी करे। कॉमर ने न्याय विभाग की आला अधिकारी अर्दोर्नी ज़नरल पाम बॉन्डी को भेजे समन में यह उल्लेख किया है। क्लिंटन दंपति के अलावा, रिपब्लिकन नेतृत्व वाले पैन्ल ने जेम्स कॉमी, लोरेटा लिंच, एरिक होल्डर, मेरिक गार्लैंड, रॉबर्ट म्यूलर, विलियम बार, जेफ सेशंस और अलबर्ट गोआलेस के बयान दर्ज कराने के लिए भी समन जारी किए हैं। कमेटी के रिपब्लिकन सदस्यों ने कहा कि वे इन लोगों से एपस्टीन संबंधी फाइलों के संबंध में जानकारी मांग रहे हैं। कुछ रिपब्लिकन वर्षों से एपस्टीन मामले से जुड़ी साजिशों और षड्यंत्रों को हवा दे रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस पर अपनी राय दे चुके हैं। कुछ ने सवाल उठया है कि इन दोनों की कथित ग्राहक सूची में और कौन हो सकता है। न्याय विभाग और एफबीआई ने पिछले महीने एक संक्षिप्त बयान में कहा था कि समीक्षा में पाया गया कि ऐसी कोई सूची मौजूद नहीं है।

ट्रंप की चेतावनी- यूरोपीय संघ ने निवेश का वादा नहीं निभाया तो लगोगा 35 प्रतिशत टैरिफ

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूरोपीय संघ (ईयू) को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि यदि यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत 600 अरब डॉलर का निवेश पूरा नहीं करता है, तो अमेरिका उसकी वस्तुओं पर 35 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगाएगा। एक जनसभा में ट्रंप ने ने कहा, उन्होंने (ईयू) अपने टैरिफ घटाए। उन्होंने हमें 600 अरब डॉलर दिए, जिसके बदले मैंने उनके टैरिफ 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिए। कुछ देशों ने पूछा कि उन्हें कम टैरिफ क्यों मिल रहा है, तो मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे 600 अरब डॉलर दिए।ट्रंप ने दावा किया कि यह रकम उनहार की तरह है, न कि कोई ऋण। यह पैसा हम किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। ईयू ने वर्षों से हमारा शोषण किया है, अब समय है कि वे इसकी भरपाई करें। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह उनके तर्क सुनने को तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल (दवा) उद्योग को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, वे फार्मा उत्पादों से भारी मुनाफा कमाते हैं, और उन्हें चीन और आयरलैंड जैसे देशों में बनाते हैं। मैं अगले एक-दो हफ्तों में इन पर अलग से टैरिफ की घोषणा करूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह टैरिफसमझौता 15 प्रतिशत टैरिफ से अलग होंगे और इन्हें वहविशेष श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं।

वृत्ति वाले देशों के उत्पादों और सेवाओं का भारत में बढ़ता उपयोग केवल हमारी अर्थव्यवस्था के बल्कि सुरक्षा के लिए भी घातक है। मैं का मानना है कि भारतीयों को विदेशी खचिली शायियाँ से बचन चाहिए, विदेशी खचन विद्यालयों की होड़ छोड़नी चाहिए और स्थानीय कारीगरों तथा उत्पादों के प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे देश की विदेशी मुद्रा की रक्षा होगी और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

हंसिका मोटवानी

सोहेल की शादी पर बनी थी वेब सीरीज, इस ओटीटी पर है मौजूद

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में कई फिल्मों में चुकी एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी इन दिनों चर्चा में हैं। हंसिका मोटवानी के तलाक की खबरें आ रही हैं और हाल ही में हंसिका ने अपने सोशल मीडिया से शादी की तस्वीरें हटाई हैं। उनकी इस एक्टिविटी से फैंस कयास लगा रहे हैं कि हंसिका और उनके पति सोहेल कथूरिया के बीच चीजें सही नहीं हैं और तभी उनके। हालांकि, कपल ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। 2022 में हंसिका ने सोहेल से शानदार तरीके से शादी की थी, जिसकी एक वेब सीरीज भी बनी थी। हंसिका और सोहेल की शादी पर बनी वेब सीरीज का नाम 'हंसिका लव शादी ड्रामा' था। इस वेब सीरीज में हंसिका-सोहेल की शादी की सभी रसमें देखने को मिलीं और इस सीरीज को फैंस ने खूब प्यार दिया। हंसिका की शादी कब हुई, वो वेब सीरीज किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? आइए जानते हैं।

'हंसिका लव शादी ड्रामा' किस ओटीटी पर देख सकते हैं ?

7 फरवरी को 'हंसिका लव शादी ड्रामा' का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसका पोस्ट 6 फरवरी को जियोहॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसके कैप्शन में लिखा गया, 'समय आ रहा है आने का, हंसिका लव शादी ड्रामा का ट्रेलर कल आएगा।' ये 10 फरवरी से हॉटस्टार ओटीटी पर स्ट्रीम करने लगा था, जिसे आज भी आप सबस्क्रिप्शन के साथ देखा देख सकते हैं। इस पोस्ट में हंसिका दुल्हन के रूप में नजर आई थीं।



'हंसिका लव शादी ड्रामा' वेब सीरीज का पहला एपिसोड 10 फरवरी को स्ट्रीम हुआ था और इस सीरीज में 6 एपिसोड्स थे। इस सीरीज को हिंदी, इंग्लिश के अलावा तेलुगू और तमिल में भी डब किया गया था। इसके पीछे की वजह ये थी कि हंसिका मोटवानी हिंदी एक्ट्रेस तो हैं ही लेकिन उन्होंने कई तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है।

हंसिका मोटवानी ले रही हैं तलाक ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हंसिका अब अपने पति सोहेल के साथ नहीं रह रही हैं, वो अपनी मां के घर वापस आ गई हैं। वहीं खबरें ये भी हैं कि हंसिका ने अपने इंस्टाग्राम से शादी की तस्वीरें भी हटा दी हैं, जिसने भी हंसिका की शादी पर बनी वेब सीरीज देखी होगी उसने 6 एपिसोड्स में देखा होगा कि उनके बीच कैसे प्यार शुरू हुआ और शादी तक पहुंचा। सीरीज में दिखाया गया कि सोहेल ने हंसिका को पेरिस के एफिल टॉवर के नीचे प्रपोज किया था और उनकी शादी भी शाही ढंग से हुई थी।

गोल्डन टेंपल में नतमस्तक हुईं

अहाना कुमरा

सिर पर दुपट्टा और येलो सूट में अपनी सादगी से जीता फैंस का दिल

फिल्म और टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस सोशल मीडिया की दुनिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। वहीं, हाल ही में अहाना कुमरा अमृतसर के प्रसिद्ध श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण

आसमान, सुनहरी रोशनी, और आज सुबह स्वर्ण मंदिर में अत्यंत शांतिपूर्ण दर्शन। एक वार्षिक अनुष्ठान जो मुझे हमेशा शांत रखता है। सदैव आभारी, सदैव धन्य।



मंदिर) के दर्शन करने पहुंचीं, जहां से उन्होंने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। फैंस एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। अहाना ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- नीला

इसके अलावा वह वेब सीरीज और फिल्मों में अपने सशक्त किरदारों के लिए भी पहचानी जाती हैं।

शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अहाना येलो सूट में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिर पर मैचिंग दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने अपने लुक को बेहद सिंपल रखा है एक्ट्रेस गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद काफी खुश और शांतिपूर्ण नजर आ रही हैं। वह दोनों हाथ जोड़ गुरुद्वारे के सामने पोज देती नजर आ रही हैं और अपनी सादगी से फैंस का दिल जीत रही हैं। फैंस कमेंट कर अहाना की इन तस्वीरों की खूब तारीफ कर रहे हैं।

वर्कफ्रंट पर अहाना

काम की बात करें तो अहाना कुमरा ने बीते वर्षों में लिपस्टिक अंडर माय बुरका, खुदा हाफिज, और रंगबाज़ जैसे प्रोजेक्ट्स से खूब नाम कमाया है।



जब ससुर अमिताभ बच्चन की बहन बनी थीं ऐश्वर्या राय, महापल्लोप हुई थी फिल्म



हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी बहू एवं सुपरस्टार एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने लंबे और सफल करियर में खास और बड़ा नाम कमाया है। अमिताभ बच्चन जहां बॉलीवुड इतिहास के सबसे बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं, तो वहीं ऐश्वर्या की गिनती बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक के रूप में होती है। बड़े पर्दे पर ससुर-बहू की जोड़ी साथ में भी नजर आ चुकी हैं। बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ने उस समय एक फिल्म में साथ काम किया था जब ऐश्वर्या की बिग बी के बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी नहीं हुई थी। अभिषेक से शादी करने से सालों पहले ऐश्वर्या ने बिग बी के साथ में एक फिल्म की थी। इसमें ऐश्वर्या ने बिग बी की बहन का किरदार निभाया था। लेकिन, ये फिल्म महाबकवास साबित हुई थी।

जब पर्दे पर अमिताभ की बहन बनीं ऐश्वर्या

अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय की वो फिल्म है 'हम किसी से कम नहीं'। इसमें अमिताभ के किरदार का नाम डॉक्टर रस्तोगी था। जबकि ऐश्वर्या ने कोमल रस्तोगी नाम की भूमिका निभाई थी। बिग बी और ऐश्वर्या भाई-बहन के किरदार में थे। दोनों के अलावा इस पिक्चर में अजय देवगन और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स भी नजर आए थे। इसके बावजूद फिल्म टिकट खिड़की पर कोई कमाल नहीं कर पाई थी।

टिकट खिड़की पर पिट गई थी फिल्म

हम किसी से कम नहीं का डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने किया था। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म ने सिनेमाघरों में 31 मई 2002 को दस्तक दी थी। इसमें संजय दत्त ने गैंगस्टर मुन्ना भाई नाम का किरदार निभाया था जो ऐश्वर्या के किरदार कोमल से शादी करना चाहता है। हालांकि बिग का किरदार डॉक्टर रस्तोगी इसमें बड़ी अड़चन बनता है।

दर्शकों को ये कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इसलिए फिल्म टिकट खिड़की पर पिट गई थी। 23 साल पुरानी इस फिल्म पर मेकर्स ने 18 करोड़ रुपये खर्च किए थे। जबकि इसकी कमाई भी बजट के बराबर ही 18.83 करोड़ रुपये ही हो पाई थी। इस हिसाब से फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पल्लोप साबित हो गई थी।

Salman Khan से 5 गुना ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस, डेब्यू से ही मचा दिया था बवाल



हिंदी सिनेमा में हमेशा से ही ये देखने को मिला है कि एक्टर्स के मुकाबले एक्ट्रेस की फीस हमेशा से ही कम रही है। हालांकि जिस अभिनेत्री के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसने तो कभी सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स से भी ज्यादा फीस ली थी। इस एक्ट्रेस की डेब्यू फिल्म की फीस ही सलमान से पांच गुना ज्यादा थी। उनकी पहली ही फिल्म हिट साबित हुई थी और वो डेब्यू के साथ ही रातों-रात फिल्म इंडस्ट्री में छा गई थीं। हम आपसे बात कर रहे हैं एक्ट्रेस भाग्यश्री की। भाग्यश्री ने अपने बॉलीवुड करियर का आगाज सलमान खान के साथ ही किया था और वो फिल्म सलमान की भी बतौर लीड एक्टर पहली पिक्चर थी। दोनों कलाकार अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गए थे। हालांकि दोनों को डेब्यू फिल्म के लिए जो फीस मिली थी उसमें बहुत फासला था।

सलमान से 5 गुना ज्यादा थी भाग्यश्री की फीस

सलमान खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1988 की पिक्चर 'बीबी हो तो ऐसी' से की थी। जबकि लीड एक्टर के रूप में उनका डेब्यू 1989 की फिल्म 'मैंने प्यार किया' से हुआ था। इसमें उनके अपोजिट भाग्यश्री ने काम किया था। सूरज बड़जाल्या के डायरेक्शन में बनी फिल्म में एक्ट्रेस परवीन दस्तूर ने भी काम किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेकर्स ने भाग्यश्री को फिल्म के लिए डेढ़ लाख रुपये फीस दी थी।

सलमान की फीस थी सिर्फ 31 हजार

परवीन दस्तूर ने फिल्म में अपनी और सलमान खाना की फीस का खुलासा भी किया था। परवीन को मेकर्स ने 25 हजार रुप दिए थे। वहीं सलमान खान को 31 हजार रुपये मिले थे। लेकिन फिल्म की अपार सफलता के बाद सलमान खान को बड़ा तोहफा मिला था। सलमान ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी डेब्यू फिल्म के लिए फीस 31 हजार थी, लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया था।

साल की सबसे कमाऊ फिल्म थी 'मैंने प्यार किया'

मैंने प्यार किया की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई थी और इसके गानों ने भी धूम मचाई थी। डेब्यू फिल्म से ही सलमान और भाग्यश्री ने फैंस के दिल जीत लिए थे। 4 करोड़ में बनी पिक्चर ने टोटल 14 करोड़ कमाए थे और ये साल 1989 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म साबित हुई थी।

